

# एक ट्रिलियन इकोनामी में काशी का 1,55,200 करोड़ का अंशदान

फिलहाल जीडीपी में योगदान 43 हजार 900 करोड़ का

जागरण संवाददाता, वाराणसी : नव्य-भव्य श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के साथ ही बनारस को जोड़ने वाली पूर्वांचल की लगभग प्रमुख सड़कों के फोर व सिक्स लेन होने और रोजगार के बढ़ते संसाधन के कारण बनारस विकास की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहा है। जीडीपी के तब तीन सेक्टर में से प्राथमिक सेक्टर (कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन आदि) को छोड़ दें तो द्वितीयक (विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण आदि) व तृतीयक सेक्टर (होटल-रेस्टोरेंट, परिवहन-संचार, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मनोरंजन आदि) के विकास की स्थिति बहुत अच्छी है। यह प्रदेश की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश की जीडीपी एक ट्रिलियन वर्ष 2028 तक करने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है। डॉलर का मूल्य 80 रुपये तब कर रहे हुए एक ट्रिलियन आनी अस्सी लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तब किया है। बनारस को राज्य की जीडीपी एक ट्रिलियन तक लाने के लिए एक लाख 55 हजार 200 करोड़ की अर्थव्यवस्था तैयार करने का सफर तब करना है। इस तरह इसे 31.06 प्रतिशत बढ़ाना होगा। वर्तमान में बनारस का जीडीपी में योगदान 43 हजार 900 करोड़ का है।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में बनारस की अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर मंथन हुआ। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से जीडीपी ग्रोथ के संबंध में उनकी तैयार रिपोर्ट की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में शामिल सभी



जीडीपी ग्रोथ को लेकर अधिकारियों संग बैठक करते डीएम • सूचना विभाग

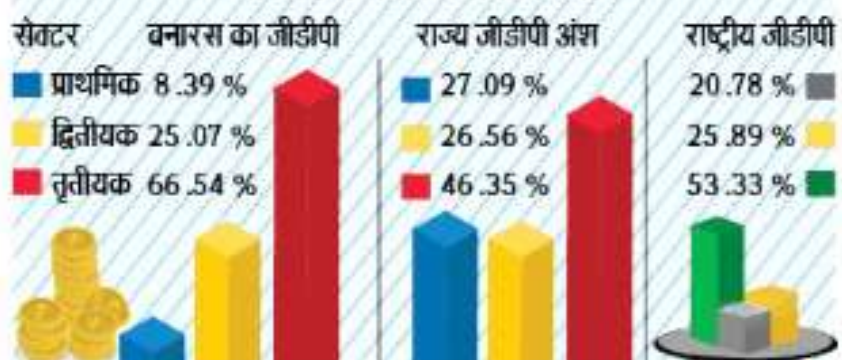
## 43,900

करोड़ वर्तमान में बनारस की जीडीपी, वर्ष 2028 तक 31% ग्रोथ की तैयारी



- पर्यटन के कारण तृतीयक सेक्टर में सबसे आगे, प्राथमिक सेक्टर में बहुत पीछे
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जीडीपी में इजाफे को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक
- समस्त विभागीय अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने का दिया गया निर्देश

### जीडीपी में बनारस का अंशदान



विभागाध्यक्षों को माइक्रो प्लान के साथ ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मत्स्य विभाग को तालाबों के पट्टों की संख्या बढ़ाने के साथ ही लक्ष्य के सापेक्ष हर महीने कितने पट्टे जारी करने होंगे। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और राजस्व विभाग से कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया। प्राथमिक क्षेत्र के कृषि, पशुधन, वानिकी, फसलें और खनन व द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य और निर्माण

कार्य व उपयोगी सेवाएं होंगी। वहीं तृतीयक क्षेत्र के व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को विभागीय कार्यक्रमों के प्रगति के साथ ही आर्थिक ढांचे को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन बनाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग बेहतर प्रयास करें।